

::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्त् एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उत्पाद शुक्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE

्दवितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road



Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in

DIN20230264\$X000000BE94



मल आदेश सं / O.I.O. No. 38/AC/NIS/BVR-3/22-23 दिनांक/Date 06-05-2022

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-021-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order; 30.01.2023

जारी करने की तारीख / Date of issue:01.02.2023

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट दवारा पारित /

Passed by Shri Shlv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तुं एवंसेवाकर,राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरित्रिखत जारी मूल आदेश से सजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rejkot / Jamnagar / Gandhidham :

अपीलकर्ता&प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of theAppellant&Respondent :-

Ashwinbhai Babubhai Suvagiya, Marutinagar, Chhatadiya Road, Taluka- Rajula-365560Dist. Amreli, Gujarat

इस आदेश(अपील) से व्यक्ति कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/ (A)

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक न 2, आरमके. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/ (i)

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावी अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए ।/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुरूक (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुरूक की मौंग, व्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कमशः 1,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये को निर्धारित जमा शुरूक की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुरूक का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक की के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक शुरूद द्वारा किया जाना चहिए जर्म। के सिर्ध के किस की अथवा स्थाप के साथ हि00/- रुपये का काम करना होगा 1/ (iii) आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst, Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित अधिनियम,1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया B) कर (उनमें से एक प्रांत प्रमाणित होनी चाहिए) आर इनमें से कम से कम एक प्रांत के सीय, जहां सवाबर का मार्ग , इवाज का मार्ग आर लगाया गया जुर्माना,रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/-रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के लाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित झफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थागन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-एत्र के खाथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed by quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be saccompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of \$1.5\$ Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than first lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is structured. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-

वत वर्गाहरू

TINE.

केम्ब्रीय

घ

वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9<u>(</u>2) (i) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुक्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

सलग्न करना हागा। /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं संवाकर अपीलीय प्राधिकरण (संस्टेट) के प्रति अपीली के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम

राम्या शुल्या, पारप्राच जरणाप सुरूप रेक रामान्य आधानियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विदादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

धारा 11 डी के अंतर्गत रकम (i)

(iii)

सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि füì

सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम बंशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

- बंशते यह कि इस धारा के प्रावधान विताय (स. 2) आधानयम 2014 के आरम स पूर्व किसा अपालाय प्राधिकारा के समक्ष विचाराधीन स्थान अज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;

(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

आरत सरकार कोष्नरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाधिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरत्क के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to subsection [1] of Section-35B ibid: (C)

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से अंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक अंडार गृह से दूसरे अंडोर गृह पारगमन के दौरान, या किसी अंडार गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के हुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनयम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)
- उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। (v) the above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OlO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए ! जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो (vi) तो रूपये 1000 - का भुगताज किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupées One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशो का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया आना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण की एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं। / In case, if the order covers various umbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-। के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. **(F)**
- उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नदीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं । / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in. (G) अपीक्ष

Share "

:: अपील आदेश / ORDER-IN-APPEAL ::

- "Appellant") has filed the present Appeal against Order-in-Original No. 38/AC/NIS/BVR-3/22-23 dated 06.05.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST Division-3, Bhavnagar (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').
- 2. The facts of the case, in brief, are that the Income Tax Department shared the third-party information/ data based on Income Tax Returns/ 26AS for the Financial year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 of the Appellant. Letters dated 18.08.2020 & 02.12.2020 were issued by the Jurisdictional Range Superintendent requesting the Appellant to provide information/documents viz. copies of 1.T. Returns, Form 26AS, Balance Sheet (including P&L Account), VAT/ Sales Tax Returns, Annual Bank Statement, Contracts/ Agreements entered with the persons to whom services provided etc. for the Financial year 2014-15, 2015-16 & 2016-17. However, no reply was received from the Appellant.
- 3. In absence of data/ information, a Show Cause Notice dated 21.12.2020 was issued to the Appellant, demanding Service Tax and cess to the tune of Rs. 8,66,892/- under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') alongwith interest under Section 75 of the Act. It was also proposed to impose penalties under Section 77(1)(a), 78, 77(2) and 77(1)(c) of the Act upon the Appellant.
- 4. The adjudicating authority vide the impugned order confirmed the demand of Rs. 5,00,772/- under Section 73(1) along with interest under Section 75 of the Act, imposed penalty of Rs. 5,00,772/- under Section 78 of the Act, imposed penalty of Rs. 2,000/- each under Section 77(1)(a), 77(2) and 77(1)(c) of the Act. The Adjudicating Authority dropped the demand of Rs. 3,66,120/-.
- 5. Being aggrieved, the Appellant has preferred the present appeal on various grounds that the Adjudicating Authority wrongly confirmed the demand, interest and wrongly imposed various penalties.
- 6. The matter was posted for hearing on 25.01.2023. CA Abhishek P Doshi appeared for personal hearing and handed over paperbook containing written submissions with supporting documents. He reiterated the submissions therein and those in the appeal. He submitted that the appellant is not a GTA but was providing transport of goods service to GTA, which is under negative list. Even if it is considered as GTA, the liability is on the recipients and not on the appellant. Therefore, he requested to set aside the Order-In-Original.

The CA on behalf of the Appellant handed over paperbook wherein it has an stated that they are proprietorship firm engaged in providing services of

Hirl

Transportation of Goods by road. The Show Cause Notice was issued on 21.12.2020 for the period 2014-15 to 2016-17. They have provided services to two parties namely M/s. Balaji Transport and other parties during these 3 years. M/s. Balaji Transport is a Goods Transport Agency to whom they have provided services. As per entry 22 of Notification No. 25/2012, the services provided to GTA are exempted from Service Tax. Further, as per Section 66D(p) of the Act, there is no tax on transportation of goods by road services except the services of GTA. In their case M/s. Balaji Transport is a GTA and there will be no Service Tax liability on transportation services provided to M/s. Balaji Transport. Even if it is presumed that, service are taxable then the liability will be on recipient of services under reverse charge mechanism as per Notification No. 30/2012-Service Tax dated 20.06.2012. M/s. Balaji Transport, the service recipient is Service Tax having Service Tax registration under registered AAKFB5665LSD001. M/s. Balaji Transport issued a letter that they are engaged in providing services of transportation of goods by road and they have availed services from the Appellant. They have also discharged Service Tax liability as applicable. M/s. The Adjudicating Authority simply rejected their submission by stating that corresponding S.T.-3 returns and challans of the recipients were not submitted.

- 6.2 The Show Cause Notice based on ITR/26As is not valid as the same has been issued in usual course of charges only related to appellant's information and with nothing more emphasized on the nature of activity to be classified under a particular service. They rely on CESTAT Delhi judgment in the case of Deltax Enterprises Vs. CCE, Delhi 2018 (10) GSTL 392 (Tri.-Del), Faquir Chand Gulati Vs. Uppal Agencies Pvt. Ltd. 2008 (12) STR 401 (S.C.), Krishna Construction Co. Vs. CCE & S.T. Bhavnagar, Final Order No. A/10973/2022 CESTAT- Ahmedabad, Kush Constructions Vs. CGST Nacin- 2019 (24) GSTL 606 (Tri.-All), Luit Developers (P) Ltd. Vs. Commissioner of CGST & Central Excise Dibrugarh 2022 (136) taxmann.com 109 (Kolkata-Cestat).
- on ITR/Form 26AS which is available with the Government and hence the allegation of suppression cannot be made and they placed reliance on decision in the case of Pappu Crane Service Vs. Commissioner of Service Tax Appeal No. 70707 of 2018-DB, Luit Developers (P) Ltd. Vs. Commissioner of CGST & Central Excise Dibrugarh 2022 (136) taxmann.com 109 (Kolkata-Cestat). The Show Cause Notice does not have any evidence to show that the Appellant suppressed any information with an intention to evade payment of Service Tax. The Show Cause Notice dated 21.12.2020 for the period 2014-15 to 2016-17 is barred by limitation as period of 5 years for 2014-15 was over by March-2020. The



M

Adjudicating Authority has wrongly charged interest and imposed penalties. They relied on the case of Hindustan Steel Ltd. Vs. State of Orissa - 2002-TIOL-148-SC-CT-LB and Commissioner of Service Tax Vs. Motorworld and others- 2012-TIOL-418-HC-KAR-ST.

- 7. I have carefully gone through the case records, impugned order and appeal memorandum filed by the Appellant. I find that Show Cause Notice had been issued without verifying any data or nature of services provided by the Appellant as the same had been issued only on the basis of data received from the Income Tax department. The Adjudicating Authority has confirmed the demand of Service Tax vide impugned order after considering the reply filed by the Appellant.
- 8. I find that the main issue that is to be decided in the instant case is whether the activity carried out by the Appellant is covered under exemption and as to whether the amount received for providing the services is taxable, or otherwise.
- On verification of profit & loss account for the year 2014-15, 2015-16 & 9. 2016-17, it is seen that there is transport income on which Service Tax has been demanded in the Show Cause Notice. The Appellant produced sample copies of bills issued to M/s. Balaji Transport for transportation of quarry material from stone crusher to Pipavav Port. Further, they have produced copy of Service Tax registration certificate in respect of M/s. Balaji Transport who is registered as Goods Transport Agency having registration No. AAKFB5665LSD001. They have also produced copy of certificate issued by M/s. Balaji Transport to the effect that they have received transport service from the Appellant and paid Service Tax on it. The Appellant issued bills to M/s. Balaji Transport on monthly basis for transportation of quarry material from stone crusher to Pipavav Port. The rate of transportation is per metric ton basis. Thus, it is clear that the Appellant provided services to Goods Transport Agencies and the said service is exempted by way of Sr. No. 22 of Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20.06.2012. The relevant excerpt is as under:

"22. Services by way of giving on hire -

- (a) to a state transport undertaking, a motor vehicle meant to carry more than twelve passengers; or
- (b) to a goods transport agency, a means of transportation of goods;"

Thus, the Appellant is not liable to pay Service Tax on the income earned on providing services to the Goods Transport Agencies.

10. The Appellant stated that since they have provided services to Goods Transport Agency and hence has not issued any consignment notes etc. and transportation activity was carried out on oral understanding with his customers.



Mind

Therefore, it appears that the services provided by him are squarely covered under Section 66D(p)(i)(A) which is re-produced below for reference:

"SECTION 66D. Negative list of services.— The negative list shall comprise of the following services, namely:—

- (p) services by way of transportation of goods—
- (i) by road except the services of-
- (A) a goods transportation agency; or
- (B) a courier agency;"

On plain reading of the above provisions, it is amply clear that services by way of transportation of good by road excluding services of a goods transportation agency are covered under negative list. As enumerated above, the services provided by the Appellant are not as a Goods Transport Agency services. Therefore, the services provided by the Appellant are well within the ambit of Section 66D(p)(i)(A) of the Act and hence the Appellant is not liable to any service tax.

- 11. In view of discussions and finding, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the Appellant.
- 12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।
- 12. The appeal filed by Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

(शिव प्रताप सिंह)/(Shiv Pratap Singh),

आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

Superintendent

By R.P.A.D. Central GST (Appeals)
Rajkot

To.

M/s. Ashvinbhai Babubhai Suvagiya, Village: Trakuda, Taluka:

Khambha, Dist.: Amreli, Pin-365550

सेवा में,

मे अश्विनमाई बाबुभाई सुवागीया, गाँव:

त्राकुड़ा, तालुकाः खांभा, जिल्लाः अमरेली,

पिन: 365550.

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेत्।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेत्।
- 3) अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल-३, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ∕5) गार्ड फ़ाइल।

